रामचन्द्र कृष्ण भट्ट

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या(यें) 7119-7120/2000)

14 मार्च 2008

[तरुण चटर्जी और पी. सदाशिवम, न्यायाधीशगण]

भूमि सुधार*:*

मंदिर से संबंधित भूमि - भूमि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को अधिभोग अधिकार प्रदान किया - अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने माना कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति थी और भूमि अधिकरण अधिभोग अधिकार देने से पहले गांव में और देवता को सार्वजनिक नोटिस देने में विफल रहा और अपीलार्थी के कब्जे की प्रकृति को किरायेदार नहीं माना जा सकता - यहां तक कि अपीलार्थी की यह दलील भी कि वह किरायेदार था, उस मुकदमे में खारिज कर दी गई जो अंतिम हो गया था - अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक निष्कर्ष के मद्देनजर, संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी - कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम*, 1961* - धारा *48* ए*, 121, 133.*

मंदिर के स्वामित्व वाली प्रश्नगत भूमि मंदिर में पूजा करने वाले 'एम' को किराएदारी के आधार पर खेती के लिए दी गई थी। उनके तीन बेटें थे। उनकी मृत्यु के बाद, उनके सबसे बड़े बेटे ने पूजा करना और भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया, और उसकी मृत्यु पर, यह काम दूसरे बेटे द्वारा किया गया। तीसरे पुत्र का निधन हो गया। दूसरे बेटे, प्रत्यर्थी संख्या **2**, की मृत्यु के बाद, सबसे बड़े बेटे के बेटे ने पूजा और खेती

करना शुरू कर दिया। 1940 में, उन्होंने अपने अधिकार त्याग दिए और ज़मीनें मंदिर अधिकारियों को सौंप दीं और गाँव छोड़ दिया। 1943 में, मंदिर के अधिकारियों ने अपीलार्थी, जो 'एम' के तीसरे बेटे का बेटा था, को और उसकी माँ को काम सौंपा दिया।

1953 में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने संयुक्त परिवार की संपत्तियों के विभाजन और कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसे संपत्तियों को त्यागने और चैरिटी कमिश्नर (पूर्त आयुक्त) की मंजूरी के अभाव में खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उसके विरुद्ध उठाई गई आपत्ति अस्वीकार कर दी गई। 1963 में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वाद भूमि के विभाजन और कब्जे के लिए एक वाद दायर किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जिसके लंबित रहने के दौरान कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि किरायेदारों के पास या उनके कब्जे में मौजूद सभी कृषि भूमि सभी विल्लंगमों (भारों) से मुक्त होकर सरकार में निहित हो जाएगी।

अधिनियम की धारा 133 में प्रावधान है कि केवल अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास किरायेदारी के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। अपीलार्थी ने अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अधिभोग अधिकार देने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। इस बीच, न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित होने के दौरान, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की दूसरी अपील स्वीकार की और हिस्सेदारी तय करके गुणागुण के आधार पर निपटान के लिए मामले को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। 1974 में, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया और माना कि अपीलार्थी किरायेदार था और उसे अधिभोग अधिकार प्रदान किया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 ने रिट याचिका दायर की।

प्रतिप्रेषित वाद की डिक्री की गई। तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 को वाद संपत्तियों में 2/3 हिस्से का हकदार माना गया।

प्रत्यर्थी संख्या 2 की रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी और मामला न्यायाधिकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को अधिभोग अधिकार प्रदान किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने रिट याचिका दायर की, जिसे अपील प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया। अपील प्राधिकरण ने यह कहते हुए अपील की अनुमति दी कि विवादित भूमि तीनों पक्षों की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. अपील प्राधिकरण ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम की धारा 48 ए के अनुसार, धारा 48 के तहत दायर आवेदन में आदेश पारित करने से पहले सार्वजनिक और व्यक्तिगत नोटिस देना भूमि न्यायाधिकरण के लिए अनिवार्य है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि भूमि न्यायाधिकरण ने मंदिर के प्रतिनिधि को नहीं सुना है। धारा 48 ए की उपधारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण को उस गांव में, जिसमें भूमि स्थित है, सार्वजनिक नोटिस जारी करना होता है जिसमें मकान मालिक और भूमि में रुचि रखने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। न्यायाधिकरण का यह भी कर्तव्य है कि वह आवेदन में उल्लिखित व्यक्तियों और ऐसे अन्य लोगों को भी व्यक्तिगत नोटिस जारी करे जो उसे भूमि में रुचि रखते प्रतीत हों। अपील प्राधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष से पता चलता है कि भूमि न्यायाधिकरण गाँव या देवता मंदिर में सार्वजनिक नोटिस देने में विफल रहा। इसे

देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भूमि न्यायाधिकरण ने उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया है जो अनिवार्य है और अपील प्राधिकरण ने भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया और उसे रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि केवल अवैधता या ऐसे आदेश या कार्यवाही की नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश में, भूमि सुधार अपील प्राधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष को बहुत अच्छी तरह से नोट किया कि अपीलार्थी के कब्जे की प्रकृति को भूमि का किरायेदार नहीं माना जा सकता है, और उसके दावे के संबंध में बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि उसने तीसरे प्रत्यर्थी को उसके अधीन किरायेदार के रूप में किराया दिया। दूसरी ओर, उसकी यह दलील कि वह जमीन का किरायेदार था, को उठाने की अनुमति नहीं दी गई और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा वाद में खारिज कर दी गई, जो अंतिम हो गया था। उक्त सामग्री के आलोक में, यह पता लगाने के बाद कि अपील प्राधिकरण का यह मानना सही था कि अपीलार्थी का किरायेदारी का दावा स्थापित नहीं हुआ था और इसमें कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है, जो धारा 121 के तहत पुनरीक्षण में हस्तक्षेप की मांग करती है, उसे खारिज कर दिया। [पैरा 6-8] [109-बी, सी, डी, एफ, जी; 110-ए, बी, सी, डी]

2. भूमि सुधार अपील प्राधिकरण द्वारा निकाले गए तथ्यात्मक निष्कर्ष और उच्च न्यायालय, जो एक पुनरीक्षण प्राधिकरण है, द्वारा की गई पुष्टि, को ध्यान में रखते हुए, किसी भी स्वीकार्य सामग्री के अभाव में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 9] [110-डी, ई]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7119-7120/2000

एल.आर.आर.पी. संख्या 2810/1989 एवं सी.पी. संख्या 487/1999 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के निर्णय और आदेश क्रमशः दिनांक 15.12.1998 और 5.11.1999 से. आर.एस. हेगड़े (पी.पी. सिंह के लिए) अपीलार्थियों की और से।

एस.एन. भट्ट, एन.पी.एस. पंवार, डी.पी. चतुवेर्दी, अमित कुमार चावला और संजय आर. हेगड़े प्रत्यर्थियों की और से।

न्यायालय का फैसला पी. सदाशिवम, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

1). ये अपीलें एल.आर.आर.पी. संख्या 2810/1989 एवं सी.पी. संख्या 487/1999, क्रमशः दिनांक 15.12.1998 और 5.11.1999 को , में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के निर्णय और आदेश के खिलाफ की गई है, जिसे खारिज कर दिया गया है।

2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

कनेनहल्ली गांव, येल्लापुर तालुक की भूमि सर्वेक्षण संख्या 7/3 की माप 1 एकड़ 4 गुंटा (बगायथ) और सर्वेक्षण संख्या 56/1 की माप 21 एकड़ (आर्द्र) कृषि भूमि है और गोपाल कृष्ण देवारू मंदिर के स्वामित्व में थी। मंदिर में दैनिक पूजा करने वाले व्यक्ति को किरायेदारी के आधार पर खेती के लिए जमीनें दी जाती थीं। अलग से कोई किराया नहीं दिया जा रहा था। मूल रूप से महाबलेश्वर भट्ट मंदिर में पूजा कर रहे थे और भूमि पर खेती कर रहे थे। उनके तीन बेटे थे, शंभू भट्ट, नारायण भट्ट और कृष्ण भट्ट। उनकी मृत्यु के बाद, उनके सबसे बड़े बेटे, शंभू भट्ट ने मंदिर में पूजा करना और प्रश्नगत भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया। शंभू भट्ट की मृत्यु के बाद, महाबलेश्वर भट्ट के दूसरे पुत्र नारायण भट्ट ने मंदिर में पूजा करना और भूमि पर खेती करना भी शुरू कर दिया। इसी बीच, महाबलेश्वर भट्ट के तीसरे पुत्र कृष्ण भट्ट का निधन हो गया। नारायण भट्ट की मृत्यु के बाद, शंभू भट्ट के पुत्र थिमप्पा ने मंदिर में पूजा करना और भूमि पर खेती करना भी शुरू कर दिया। वर्ष 1940 में,

प्रत्यर्थी संख्या 2, थिमप्पा भट्ट ने अपने अधिकारों को त्याग दिया और भूमि को मंदिर के अधिकारियों को सौंप दिया और गांव छोड़ दिया और वहां अन्य भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया। वर्ष 1943 में, मंदिर के ट्रस्टियों ने मंदिर में पूजा करने और भूमि पर खेती करने का अधिकार यहां अपीलकर्ता रामचंद्र कृष्ण भट्ट और उसकी मां को सौंप दिया। अपीलकर्ता कृष्ण भट्ट का पुत्र है। 10/2/1948 को, अपीलकर्ता की मां का नाम अधिकार अभिलेख में एस वाई क्रमांक 7 /3 के संरक्षित किरायेदार के रूप में और अपीलकर्ता का नाम एस वाई 56/1 लिए साधारण किरायेदार के रूप में क्रमशः प्रविष्टि संख्या 198 और 238 द्वारा दर्ज किया गया था। वर्ष 1953 में, थिमप्पा भट्ट, प्रत्यर्थी संख्या 2, ने संयुक्त परिवार की संपत्तियों के विभाजन और कब्जे के लिए सिविल जज, जूनियर डिवीजन, हलियाल के समक्ष वाद संख्या ओ.एस. 19/1953 के तहत वाद दायर किया। वादपत्र में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्वीकार किया कि वह अपनी बहन की संपत्ति की देखभाल के लिए गांव छोड़कर हितल्ली गांव चला गया था। 31.5.1958 को, विचारण न्यायालय ने माना कि जहां तक निर्धारित भूमि का संबंध है, संपत्तियों को श्री गोपाल कृष्ण देव मंदिर की पूजा के लिए आवंटित किरायेदारी भूमि के रूप में दिखाया गया था। विचारण न्यायलय ने यह भी माना कि वादी (यहां प्रत्यर्थी संख्या 2) ने वाद के उद्देश्य के लिए अपना दावा छोड़ दिया था और यह वाद जहां तक इन जमीनों से संबंधित है, चैरिटी कमिश्नर (पूर्त आयुक्त) की मंजूरी के अभाव में अक्षम माना जाता है। शेष अचल संपत्तियों के संबंध में कोई विवाद नहीं था और इसे विभाजित करने का आदेश दिया गया था। यहां अपीलकर्ता की मां की मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता का नाम दिनांक 27/8/1961 को अधिकारों के अभिलेख में दोनों सर्वेक्षणों के संबंध में संख्या 303 के तहत दर्ज किया गया था। इस संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आपत्ति उठाई गई थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, वर्ष 1963 में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वाद भूमि के विभाजन और कब्जे के लिए 1963 के

ओ.एस. संख्या 70 के रूप में एक और वाद दायर किया। वाद दायर करने से पहले, उन्होंने वाद भूमि के विभाजन के लिए वाद दायर करने की अनुमति के लिए चैरिटी आयोग में आवेदन किया था। उक्त अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। 1963 के ओ.एस. संख्या 70 को भी ख़ारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष आर.एस.ए. संख्या 930/1973 के तहत अपील दायर की।

3). दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) में संशोधन किया गया और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया कि किरायेदारों के पास या उनके कब्जे में मौजूद सभी कृषि भूमि सभी विल्लंगमों (भारों) से मुक्त होकर सरकार में निहित हो जाएगी। धारा 45 किरायेदारों को अधिभोग अधिकारों की मंजूरी के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 48 ए में किरायेदार द्वारा जांच आदि कराने वाले न्यायाधिकरण में आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है। धारा 133 में प्रावधान है कि अकेले अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास किरायेदारी के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा और धारा 132 न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है। अपीलकर्ता ने अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए फॉर्म संख्या 7 में एक आवेदन दायर किया। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा स्वयं के लिए या संयुक्त परिवार की ओर से अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। इस बीच, भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर 1973 के आरएसए संख्या 930 पर विचार किया और अपील की अनुमति देते हुए, हिस्सा तय करते हुए गुणागुण के आधार पर मामले को निपटान के लिए विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर दिया। 5.11.1974 को

अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता 1.3.1974 को किरायेदार था और तदनुसार अपीलकर्ता को अधिभोग अधिकार प्रदान किया। उक्त आदेश के खिलाफ, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 19619/1979 दायर की। प्रतिप्रेषित वाद जिसे 1979 के ओ.एस. संख्या 34 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था, उस पर 18/12/1980 को फैसला सुनाया गया था कि प्रतिवादियों ने विवाद्यक संख्या 5 को छोड़कर सभी विवाद्यकों (मुद्दों) का अवलोकन नहीं किया और जहां तक विवाद्यक संख्या 5 का संबंध है, वाद बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ फ्रैग्मेंटेशन एंड कंसॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट से प्रभावित नहीं था। तदनुसार, वादी - थिमप्पा (यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2) को दोनों सर्वेक्षणों में 2/3 हिस्सेदारी का हकदार माना गया। 9.6.1983 को उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देकर डब्ल्यू. पी. संख्या 19619/1979 में एक आदेश पारित किया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायाधिकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया। न्यायाधिकरण ने आवेदन पर नए सिरे से विचार किया और अधिनियम और नियमों में अनुध्यात तरीके से जांच की। 16.8.1985 को, न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलकर्ता अकेले नियत तिथि पर किरायेदार के रूप में भूमि पर खेती कर रहा था और मंदिर भूमि का मालिक था और तदनुसार अपीलकर्ता को अधिभोग अधिकार प्रदान किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। अपील प्राधिकरण के गठन के परिणामस्वरूप, मामला उक्त प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ अंतरित किया गया था और डीएएए: एपी: 244.330/86 के रूप में पंजीकृत किया गया था। 31.1.1989 को, अपील प्राधिकरण ने माना कि भूमि किरायेदारी भूमि थी, इसलिए, अपील की अनुमति दी और न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने उच्च

न्यायालय के समक्ष 1989 की एलआरआरपी संख्या 2810 दायर की जिसे आदेश दिनांक 15/12/1998 द्वारा खारिज कर दिया गया। 5.11.1999 को अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। इसलिए, उक्त आदेशों से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील दायर की।

4). अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्रीमान आर.एस. हेगड़े और प्रत्यर्थियों के वकील श्री एस.एन. भट्ट को सुना.

5). अपीलकर्ता की शिकायत है कि यद्यपि भूमि न्यायाधिकरण ने, दिनांक 16.08.1985 के आदेश द्वारा, सर्वेक्षण संख्या 56/1 में 2-21-0 की सीमा तक और 7/3 में 1-4-0 की सीमा तक कन्नेनाल्ली गाँव के भूमि के संबंध में उसके पक्ष में अधिभोग अधिकार घोषित किया और प्रदान किया। भूमि सुधार अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने और उक्त भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार की मांग करने वाले अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज करने में त्रुटि की। पहले के अनुच्छेदों में तथ्यों के वर्णन को देखते हुए उन्हें दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि अपीलकर्ता, जो कृष्ण भट्ट के पुत्र और महाबलेश्वर भट्ट के पोते हैं, द्वारा किए गए आवेदन पर कर्नाटक भूमि न्यायाधिकरण ने यह पाया कि प्रश्नगत भूमि मंदिर की भूमि है जिस पर आवेदक (यहाँ अपीलकर्ता) द्वारा अपनी मंदिर सेवा के काम के लिए खेती की जा रही है और 1944 से लगातार इन जमीनों पर खेती की जा रही है, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह उन जमीनों पर खेती कर रहा है जो मंदिर की किरायेदार के रूप में हैं और इसलिए, वह है अधिभोग अधिकार का हकदार है. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, महाबलेश्वर नारायण भट्ट और थिमप्पा भट्ट, क्रमशः शंभू भट्ट और नारायण भट्ट के पुत्र और महाबलेश्वर भट्ट के पोतो ने भूमि सुधार अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील

दायर की। सामग्री, विशेष रूप से सिविल कोर्ट के फैसले और डिक्री के साथ-साथ प्राधिकरण के आदेशों का विश्लेषण करने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित भूमि तीनों पक्षों, अर्थात्, रामचंद्र कृष्ण भट्ट, महाबलेश्वर भट्ट और थिमप्पा भट्ट की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि अपील प्राधिकरण 1979 के ओ.एस. संख्या 37 के तहत सिविल कोर्ट के फैसले के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अपील प्राधिकरण का निम्नलिखित निष्कर्ष प्रासंगिक है:

"...चूंकि तीसरे प्रत्यर्थी ने कोई आपत्ति नहीं की है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विवादित भूमि अपीलकर्ताओं के अविभाजित परिवार और तीसरे प्रतिवादी की किरायेदारी भूमि है। इन निर्विवाद तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि श्री गोपालकृष्ण देवता की पूजा और अन्य सेवाओं का अधिकार और विवादित भूमि का उपभोग तीसरे प्रत्यर्थी को नहीं दिया गया था, लेकिन किरायेदारी अधिकारों के अतिरिक्त पूजा और अन्य सेवाएं संयुक्त परिवार के अविभाजित अधिकार थे।

सिविल कोर्ट द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष और उसके समक्ष रखी गई अन्य सामग्रियों के आधार पर, अपील- प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है:

"इसलिए, तीसरे प्रत्यर्थी के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि उसका संबंधित अवधि के लिए विवादित भूमि पर कब्जा रहा है और उस पर खेती कर रहा है और वह अधिभोग अधिकारों के लिए पात्र है और हम उसके तर्क को खारिज करते हुए तदनुसार जवाब देते हैं।"

6). अपील प्राधिकरण ने उचित रूप से निर्दिष्ट किया कि अधिनियम की धारा 48 ए के अनुसार, धारा 48 के तहत दायर आवेदन में आदेश पारित करने से पहले सार्वजनिक और व्यक्तिगत नोटिस देना भूमि न्यायाधिकरण के लिए अनिवार्य है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि भूमि न्यायाधिकरण ने श्री गोपालकृष्ण देवारू मंदिर के प्रतिनिधि को नहीं

सुना है। धारा 48ए की उपधारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण को उस गांव में सार्वजनिक नोटिस जारी करना होता है जिसमें भूमि स्थित है, जिसमें मकान मालिक और भूमि में रुचि रखने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। न्यायाधिकरण का यह भी कर्तव्य है कि वह आवेदन में उल्लिखित व्यक्तियों और ऐसे अन्य लोगों को भी व्यक्तिगत नोटिस जारी करे जो उसे भूमि में रुचि रखते प्रतीत हों। उप-धारा (3) आवेदन का प्रपत्र, नोटिस का प्रपत्र और नोटिस प्रकाशित करने या तामील का तरीका निर्धारित करती है। उप-धारा (4) कहती है कि जहां कोई आपत्ति दायर नहीं की जाती है, न्यायाधिकरण, सत्यापन के बाद, आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करता है। उप-धारा (5) के अनुसार, जहां आवेदक के दावे की वैधता या प्रतिद्वंद्वी दावे की स्थापना पर विवाद करते हुए एक आपत्ति दायर की जाती है, वहाँ जांच करना और उसके बाद कब्जेदार के रूप में पंजीकृत होने के हकदार व्यक्ति का निर्धारण करना और तदनुसार आदेश पारित करना न्यायाधिकरण का कर्तव्य है। अपील प्राधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष से पता चलता है कि भूमि न्यायाधिकरण गांव में और देवता गोपालकृष्ण देवारू मंदिर को सार्वजनिक नोटिस देने में विफल रहा। इसे ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि भूमि न्यायाधिकरण ने उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया है जो अनिवार्य है और अपील प्राधिकरण ने भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया है और उसे खारिज कर दिया।

7). अपील प्राधिकरण ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी कोई स्वीकार्य सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता अकेले भूमि पर खेती कर रहा था और अधिभोग अधिकार का हकदार था।

8). उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 121 ए के तहत अपीलकर्ता द्वारा उसके समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचार किया। उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण

क्षेत्राधिकार को देखने से पता चलता है कि केवल अवैधता या ऐसे आदेश या कार्यवाही की नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में भूमि सुधार अपील प्राधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष को बहुत अच्छी तरह से नोट किया कि अपीलकर्ता के कब्जे की प्रकृति को भूमि का किरायेदार नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि उसके दावे के संबंध में बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है कि उसने अपने अधीन किरायेदार के रूप में तीसरे प्रत्यर्थी को किराया दिया था। दूसरी ओर, उनकी यह दलील कि वह जमीन के किरायेदार था, को उठाने की अनुमति नहीं दी गई और ओएस नंबर 34/79 में खारिज कर दिया गया जो अंतिम हो गया था। उक्त सामग्री के आलोक में, इस निष्कर्ष के बाद कि भूमि सुधार अपील प्राधिकरण यह मानने में सही था कि अपीलकर्ता का किरायेदारी का दावा स्थापित नहीं हुआ था और कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है जो धारा 121 के तहत पुनरीक्षण में हस्तक्षेप की मांग करती है, को खारिज कर दिया गया।

9). भूमि सुधार अपील प्राधिकरण द्वारा निकाले गए तथ्यात्मक निष्कर्ष और किसी भी स्वीकार्य सामग्री के अभाव में उच्च न्यायालय, जो कि एक पुनरीक्षण प्राधिकरण है, द्वारा की गई पुष्टि, को ध्यान में रखते हुए,

हमारा विचार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10). उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, अपीलें गुणहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। कोई हर्जा-ख़र्चा नहीं।

डी.जी. अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक रविन्द्र कुमार **(**आर.जे.एस.**)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।